भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारंकित प्रश्न संख्या : 2990
उत्तर देने की तारीख : 12.12.2024

महिलाओं के स्वामित्व वाली एमएसएमई

2990. श्री हरीश चंद्र मीना :
श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल :

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान टॉक-सवाई माधोपुर जिले और वलसाड (एसटी) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान में पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की महिला स्वामियों का राज्य-वार प्रतिशत कितना है;
- (ख) देश और विशेष रूप से उक्त राज्यों तथा उक्त जिले और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत एमएसएमई की महिला स्वामियों की वर्तमान संख्या कितनी है;
- (ग) देश और विशेष रूप से उक्त राज्यों में वर्ष 2019 और 2013 की तुलना में वर्ष 2024 में महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई की संख्या कितनी है; और
- (घ) सरकार द्वारा देश और विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में एमएसएमई में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संशोधित परिभाषा दिनांक 01.07.2020 को अपनाई गई थी। तब से लेकर दिनांक 30.11.2024 तक, देश में उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) पर महिला-स्वामित्व वाली कुल 2,20,73,675 एमएसएमई पंजीकृत हो चुकी हैं। पंजीकृत महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रतिशत तथा विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान में, उनकी संख्या, अनुबंध में दी गई है।

दिनांक 30.11.2024 तक टॉक और सवाई माधोपुर जिलों में महिला स्वामित्व वाले कुल 7,803 एमएसएमई ने यूआरपी और यूएपी पर पंजीकरण कराया है, जो राजस्थान के इन जिलों में कुल पंजीकृत एमएसएमई का 13% है।

दिनांक 30.11.2024 तक वलसाड जिले में महिला-स्वामित्व वाले कुल 11,942 एमएसएमई ने यूआरपी और यूएपी पर पंजीकरण कराया है, जो कि गुजरात के वलसाड जिले में कुल पंजीकृत एमएसएमई का 18.24% है।

(ग) : दिनांक 30.11.2024 तक देश में और गुजरात एवं राजस्थान राज्यों में यूएपी सहित यूआरपी पर पंजीकृत महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई का विवरण निम्नानुसार है:

महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई की संख्या		
वित्त वर्ष	वर्ष 2020-21 (01.07.2020 से 31.03.2021 तक)	सकल योग (30.11.2024 तक)
अखिल भारत	4,87,287	2,20,73,675
गुजरात	37,146	9,12,052
राजस्थान	29,371	8,15,207

(घ) : सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गुजरात और राजस्थान राज्य सहित देश में एमएसएमई में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि के लिए कई प्रयास किए हैं। वे निम्नानुसार हैं:

- (i) महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान।
- (ii) महिला उद्यमियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से, वर्ष 2018 में सार्वजनिक खरीद नीति में संशोधन किया गया, जिसके तहत केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों को अपनी वार्षिक खरीद का कम से कम 3% महिला उद्यमियों से क्रय करना अनिवार्य कर दिया गया है।
- (iii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए, वार्षिक गारंटी शुल्क में 10% की रियायत दी जाती है; अन्य उद्यमियों के 75% की तुलना में महिला स्वामित्व वाले एमएसई को 90% गारंटी कवरेज दी जाती है।
- (iv) एमएसएमई मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन करता है, जो कि मुख्य रूप से ऋण-संबंधी सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर का सृजन करना है। इस योजना के तहत साधारण श्रेणी के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी दर, शहरी क्षेत्रों में 15% और ग्रामीण क्षेत्रों में 25% है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक, महिलाएं, सेवानिवृत्त सैनिक, दिव्यांगजन तथा पूर्वोत्तर, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों के विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी, शहरी क्षेत्रों में 25% और ग्रामीण क्षेत्रों में 35% है।
- (v) खरीद और विपणन सहायता योजना के अंतर्गत व्यापार मेलों में महिला उद्यमियों की सहभागिता को 100% सब्सिडी दी जाती है, जबकि अन्य उद्यमियों को 80% सब्सिडी दी जाती है।
- (vi) महिलाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय कयर विकास योजना के तहत 'कौशल उन्नयन और महिला केंयर योजना' लागू करता है, जो केंयर क्षेत्र में कार्यरत महिला कारीगरों के कौशल विकास के उद्देश्य से एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
- (vii) एमएसएमई मंत्रालय ने 27.06.2024 को 'यशस्विनी अभियान' की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य औपचारिकता, ऋण क्षमता निर्माण और इन योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके मार्गदर्शन पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूरे भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2990, जिसका उत्तर दिनांक 12.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 30.11.2024 तक, महिला-स्वामित्व वाली एमएसएमई और संबंधित राज्य में यूआरपी और यूएपी पर पंजीकृत उनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रतिशत			
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महिला स्वामित्व वाली एमएसएमई	महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई का प्रतिशत
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4,655	27%
2	आंध्र प्रदेश	1,332,126	53%
3	अरुणाचल प्रदेश	11,683	43%
4	असम	331,016	35%
5	बिहार	1,525,287	50%
6	चंडीगढ़	14,304	24%
7	छत्तीसगढ़	412,172	42%
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	6,739	25%
9	दिल्ली	276,746	27%
10	गोवा	38,561	39%
11	गुजरात	912,052	28%
12	हरियाणा	390,068	27%
13	हिमाचल प्रदेश	52,568	22%
14	जम्मू और कश्मीर	154,080	23%
15	झारखंड	550,417	48%
16	कर्नाटक	1,656,845	45%
17	केरल	606,823	47%
18	लद्दाख	4,872	29%
19	लक्षद्वीप	446	23%
20	मध्य प्रदेश	1,349,621	38%
21	महाराष्ट्र	2,535,077	35%
22	मणिपुर	65,068	53%
23	मेघालय	16,810	45%
24	मिजोरम	24,140	60%
25	नागालैंड	26,858	53%
26	ओडिशा	779,711	44%
27	पुडुचेरी	40,235	49%
28	पंजाब	491,259	31%
29	राजस्थान	815,207	25%
30	सिक्किम	10,046	46%
31	तमिलनाडु	1,926,040	43%
32	तेलंगाना	948,659	45%
33	त्रिपुरा	162,406	66%
34	उत्तर प्रदेश	1,968,385	33%
35	उत्तराखंड	146,090	31%
36	पश्चिम बंगाल	2,486,603	62%
	कुल:-	22,073,675	40%

रिपोर्ट दिनांक :- 09.12.2024 02:10 सायं